भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.556

दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तरार्थ

पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र

556. श्री भुपेन्द्र यादव: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी अनुसूची में यथा चिन्हित उन अनुसूचित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जहां पर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम,1996 के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया है; और

(ख) विगत पांच वर्षो के दौरान इन क्षेत्रों में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई है ?

उत्तर

पंचायती राज, राज्य मंत्री
(श्री परषोत्तम रूपाला)

(क) राज्यवार अधिसूचित पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के जहां संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायतों का गठन (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के अधीन किया गया है, **परिशिष्ट-I** पर दिए गए है ।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं । बहुत से राज्य सरकारों ने अपने पंचायती राज अधिनियमों को पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया है । आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों ने अपने राज्य विशिष्ट पेसा नियम बनाए हैं । मंत्रालय की पहले की राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना (आरजीपीएसए) राज्यों की वार्षिक योजनाओं पर आधारित थी । पांचवी अनुसूची क्षेत्र की पंचायतों को निकट सहयोग देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षिण, ग्राम सभा संघटकों और पेसा संयोजको की तैनाती के लिए सहायता प्रदान की गई । राज्यों में सभी हितधारकों, सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए आठ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उनसे आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई ।

****

अनुबंध-I

पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 556 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं	**राज्य का नाम**	**ग्राम / ग्राम पंचायत**	**मध्यवर्ती पंचायतों**	**जिला**	
				पूरी तरह से कवर	**आंशिक रूप से कवर**
1	आंध्र प्रदेश	588	36	0	5
2	छत्तीसगढ़	5050	85	13	6
3	गुजरात	2388	40	4	7
4	हिमाचल प्रदेश	151	7	2	1
5	झारखंड	2074	131	13	3
6	मध्य प्रदेश	5211	89	5	15
7	महाराष्ट्र	2835	59	0	12
8	ओडिशा	1921	119	6	7
9	राजस्थान	4544	26	2	3
10	तेलंगाना	631	72	0	4
	कुल	**25393**	**664**	**45**	**63**

*****